

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने की फायरिंग

● सुरक्षा बलों ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब,सर्च ऑपरेशन जारी

किश्तवाड़ (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर वन क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी है। इस बाद बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि दोपहर को चतुरक्ष क्षेत्र के मन्द्रल-सिंचूरा के पास सोननार गांव में



घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान गोलीबारी शुरू हुई। इलाके में अतिरिक्त बलों को भेजा गया है तथा विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। सूत्रों की मानें तो यहां जैश के आतंकी छिपे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार, आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी के बाद, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया। घने जंगल वाले इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। सूत्रों के अनुसार, माना जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों का एक समूह इलाके में फंसा हुआ है। हालाँकि, आतंकवादियों की पहचान और संख्या के बारे में आधिकारिक पुष्टि का अभी भी इंतजार है।

35 करोड़ लोगों की सेहत की जिम्मेदारी उठा रहा यूपी

● लखनऊ में बोले सीएम योगी,हेल्थटेक कॉन्वलेव का किया आगाज

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी सिर्फ 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य ही नहीं, देश के सबसे बड़े हेल्थकेयर कंज्यूमर मार्केट के रूप में ये 35 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का भार वहन करता है। इनमें कई पड़ोसी राज्य के मरीज भी शामिल है। जिनका यहां पर इलाज होता है। ये कहना है, सीएम योगी आदित्यनाथ का। रविवार को वो लखनऊ में यूपी हेल्थटेक कॉन्वलेव 1.0 का



शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर इनोवेशन और फार्मा मैनुफैक्चरिंग का राष्ट्रीय और वैश्विक हब बनाने की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले पाँच नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है, जिसके परिणाम आज जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पाँच नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में वह परिवर्तन किया है, जिसकी कल्पना पहले संभव नहीं थी। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर कुल 40 मेडिकल कॉलेज थे।

बवाल मचा तो विधायक बरैया खुद के बयान से पलटे

कहा- मैंने बिहार के प्रोफेसर की किताब में पढ़ा, मंत्री बागरी बोलीं, ये निशाचरों की भाषा है

भोपाल (नप्र)। दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक विवादित बयान को लेकर गंभीर राजनीतिक और सामाजिक विवादों में घिर गए हैं। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार को लेकर दी गई उनकी तथाकथित ‘श्वोरी’ पर चौतरफा निंदा हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी उनके बयान से दूरी बना ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फूल सिंह बरैया से लिखित स्पष्टीकरण तलब किया है। वहीं, बढ़ते विरोध के बाद खुद बरैया ने अपने बयान से किनारा कर लिया है।

बरैया बोले : मैं उस बयान से खुद सहमत नहीं हूँ

फूल सिंह बरैया ने एक वीडियो जारी कर कहा- जिस बयान को लेकर मेरे



ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह मेरा मौलिक बयान नहीं है। वह बयान बिहार में दर्शनशास्त्र के एचओडी रहे हरिमोहन झा द्वारा लिखा गया है। मैंने उसे एक संदर्भ में कोट किया है। मैं उस बयान से

भी सहमत नहीं हूँ। मैं स्वयं ऐसा नहीं मानता, लेकिन संदर्भ के तौर पर उसे उद्धृत किया गया था।

मंत्री प्रतिमा बागरी ने भी साधा बरैया पर निशाना

मध्यप्रदेश सरकार की नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने इस बयान को निशाचरों की भाषा करार दिया। प्रतिमा बागरी ने एससी-एसटी-ओबीसी महिलाओं को धमके से जोड़कर दुकर्म को कथित रूप से पुण्य बताने की श्वोरी को सिर से खारिज करते हुए कहा कि यह न धर्म है, न पुण्य-यह सीधा-सीधा पाप है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस तरह की बातों का कोई उल्लेख नहीं है।यह सोच धर्मग्रंथों की नहीं, बल्कि निशाचारी और तांत्रिक प्रवृत्तियों की देन है, जहां मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता।

दुष्कर्म को धर्म से जोड़ना पीड़िताओं का अपमान

राज्यमंत्री ने भावुक शब्दों में कहा कि दुकर्म करने वाला व्यक्ति अपराध कर सम्मान के साथ चला जाता है और उसे धर्म से जोड़ना पीड़िताओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म कहीं भी ऐसे कृत्यों का समर्थन नहीं करता। भारतीय संस्कृति त्याग, तपस्या और नारी सम्मान पर आधारित है। नारी को जन्म देने वाली माता के रूप में पूजा गया है, जिनके पुण्य से पृथ्वी टिकी है।प्रतिमा बागरी ने अंत में फूल सिंह बरैया के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि समाज, महिलाओं और पुरुषों को मिलकर ऐसी सोच का विरोध करना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा देने वालों को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि समाज इस बुराई के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो।

बसंत पंचमी पर विवाह मुहूर्त नहीं, परंपरा में बदलाव

शुक्र का तारा अस्त होने से इस साल बसंत पंचमी पर कोई शुभ कार्य नहीं होंगे

उज्जैन (नप्र)। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को अबुल्ल मुहूर्त मानकर देशभर में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य किए जाते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष बसंत पंचमी पर विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है। 23 जनवरी, शुक्रवार को आने वाली बसंत पंचमी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, परिघ योग तथा कुंभ के उपरांत मीन राशि में चंद्रमा की साक्षी में रहेगी। धर्मशास्त्र के अनुसार, शुक्र या गुरु का तारा अस्त होने पर विवाह जैसे संस्कार वर्जित माने जाते हैं। इसी कारण इस बार बसंत पंचमी पर विवाह का मुहूर्त नहीं बन रहा है। ज्योतिषाचार्य बोले- इस बार परिस्थितियां अलग हैं- उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डिब्बेवाला के अनुसार, माघ मास में बसंत पंचमी को अबुल्ल मुहूर्त मानकर पंचमी को बसंत पंचमी कहा जाता है। इसी दिन खटवांग जयंती और तक्षक पंचमी का भी



संयोग रहता है। सामान्यतः इस तिथि को विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य शुभ माने जाते हैं, किंतु शुक्र तारा अस्त होने से इस बार ये उपक्रम संभव नहीं होंगे। आमतौर पर मालवा-निमाड़ ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में बसंत पंचमी को अबुल्ल मुहूर्त मानकर मांगलिक कार्यों की परंपरा रही है, लेकिन इस बार परिस्थितियां भिन्न हैं।

अमेरिका को लगा बड़ा झटका

यूरोपीय संसद ने रोकी ट्रेड डील

ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ का दांव पड़ा उल्टा,अपनों ने घेरा

पेरिस (एजेंसी)। ग्रीनलैंड पर कब्जे की डोनाल्ड ट्रंप धमकियों को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों में तनाव बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय संसद ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील पर रोक लगा दी है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल के प्रस्ताव का विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की।

यूरोपीय संसद के इस कदम से पिछले साल हुए ट्रांसअटलांटिक समझौते पर सवालिया निशान लग गया है। इस समझौते पर पिछले साल जुलाई में राष्ट्रपति ट्रंप

और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने हस्ताक्षर किए थे। समझौते का मकसद अमेरिकी टैरिफ को 15



प्रतिशत पर रखकर व्यापार संबंधों को स्थिर करना था। इसके बदले में अमेरिकी एक्सपोर्ट पर शुल्क को कम किया जाना था। लेकिन ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दबाव ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। ट्रंप ने

मणिपुर में 3 साल पहले

शिकार युवती की मौत

सदमे में थी, 2023 हिंसा में पहले किडनैपिंग,फिर हुई दरिदगी

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर में 3 मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू होने के तुरंत बाद गैंगरेप का शिकार हुई 20 साल की युवती की मौत हो गई है। गैंगरेप के समय वह सिर्फ 18 साल की थी। एजेंसी के अनुसार, महिला लगभग तीन साल पहले किडनैपिंग और गैंगरेप के सदमे से अब तक उबर

● अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं, कुकी समुदाय का कैडल मार्च

नहीं पाई थी। महिला की मां ने बताया कि वह गंभीर रूप से जखमी हुई थी। गंभीर चोटों के कारण उनकी बेटी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। आखिरकार, 10 जनवरी को वह जिंदगी से जंग हार गई। महिला कुकी समुदाय से थी। उसने मणिपुर के सिंगहाट में अंतिम सांस ली। पीड़ित ने 21 जुलाई, 2023 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उसने आरोप लगाया था कि 15 मई, 2023 को काले रंग की टी-शर्ट पहने चार

तांत्रिक क्रियाओं में अमरत्व जैसी बातें होती हैं

राज्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक है कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ऐसे ग्रंथों और विचारों का उल्लेख कर रहा है, जिनमें तांत्रिक क्रियाओं और अमरत्व जैसे विकृत प्रयासों की बात होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे विचार समाज, महिलाओं और मानवीय जीवन के लिए घातक हैं।

प्रतिमा बागरी ने कहा कि भारतीय समाज में महिलाओं ने त्याग, बलिदान, वीरता, शौर्य, बुद्धिमता, उद्यमिता और कार्यकुशलता के असंख्य उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बरैया को सलाह दी कि वे ऐसे विचारों का प्रचार करने के बजाय उन पुस्तकों और उदाहरणों का अध्ययन करें, जो महिलाओं के सम्मान और योगदान को रेखांकित करते हैं।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों को धर्म से जोड़कर प्रोत्साहित करना खतरनाक

प्रतिमा ने कहा कि बरैया का बयान समाज को यह संदेश देता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को धर्म से जोड़कर प्रोत्साहित किया जाए, जो बेहद खतरनाक है। यह सोच उन बच्चियों के दर्द और पीड़ा को समझने में पूरी तरह असफल है, जिनके साथ तीन-तीन साल की उम्र में जघन्य अपराध होते हैं--जब वे न जाति जानती हैं, न समाज, न धर्म।

अमेरिका नहीं तोड़ पाएगा भारत की रूस से दोस्ती

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन देशों पर टैरिफ के जरिए लगाम कसने की कोशिश कर रहे हैं जो रूस से खरीद रहे हैं। इनमें भारत भी शामिल है। उन्होंने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। इसमें 25 फीसदी सिर्फ इस कारण है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है। वहीं ट्रंप ने हाल ही में फिर से 500 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसके बाद भी भारत रूस से लगातार तेल खरीदना जारी रखेगा। ग्लोबल रियल टाइम डेटा और एनालिटिक्स कंपनी केक्लर के मुताबिक ट्रंप की 500 फीसदी टैरिफ की धमकी के बाद भी भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात जनवरी में भी मजबूत बना रहने की उम्मीद है।

इवेंट मैनेजमेंट की आड़ में हाई-प्रोफाइल ड्रग पार्टियां...15000 में एंट्री

युवतियों को पैडलर बनाकर 5 राज्यों में एमडी ड्रग बेचता था भोपाल का अबान

भोपाल (नप्र)। इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आया अबान शकील गोवा, इंदौर, मुंबई और दिल्ली में एमडी ड्रग की सप्लाई में करता था। उसके गिरोह में दो युवतियां सक्रिय रूप से पैडलर के तौर पर काम कर रही थीं। युवतियों पर शक आसानी से नहीं होता था। लिहाजा, अबान और उसका साथी बाबा शर्मा लड़कियों को मोटे कमीशन और ड्रग की फ्री खुराक का लालच देकर तस्करी के काम में जोड़ लेते थे। अबान की



निशानदेही पर दो युवतियों सहित बाबा शर्मा की भी गिरफ्तारी की गई है। इंदौर पुलिस की जांच में साफ हुआ कि अबान और बाबा शर्मा अंतरराज्यीय एमडी तस्करी गिरोह का हिस्सा हैं। चार से पांच राज्यों में सक्रिय रूप से तस्करी का काम कर रहे थे। जांच में यह भी साफ हो चुका है कि इवेंट मैनेजमेंट की आड़ में बाबा शर्मा, अलीशा मसीह और नेहा तीनों आरोपी इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। इन तीनों ने कई बड़ी पार्टीज ऑर्गनाइज की हैं, जिसमें एंट्री फीस 10 से 15 हजार रुपए तक होती थी। यहां रईसजादों को ड्रग खपाने का काम किया जाता था।

पार्टी क्लब्स के नाम पर शरा का आदी बनाया जाता था- पार्टीज के नाम पर अबान कई युवाओं को ऐसी पार्टी में लेकर पहुंचता था। बाद में इन्हें एमडी की खुराक देकर पार्टी क्लब्स के नाम पर नशे का आदी बनाया जाता था। गिरोह के चारों सदस्य मुख्य रूप से गोवा, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, मुंबई और दिल्ली में भी पार्टीज ऑर्गनाइज करते रहे हैं।

अब तक कुल चार गिरफ्तारी हो चुकी- एमडी ड्रग की तस्करी करने वाले अबान गिरोह के 3 और तस्करों को इंदौर के कनाड़िया, मुंबई और देवास से गिरफ्तार किया गया है। एमडी तस्करी मामले में अंतरराज्यीय तस्कर वैभव उर्फ बाबा ने अबान और युवतियों के साथ गिरोह बनाकर ड्रग्स तस्करी की बात स्वीकार कर ली है।

‘सिंगूर’ से बंगाल फतह की तैयारी में बीजेपी

● जिस मुद्दे ने ममता को सत्ता दिलाई,अब उसी से होगा ‘खेला’ ● टीएमसी का आरोप,पुराने घावों को कुरेदने की कोशिश में बीजेपी

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले सिंगूर मुद्दा एक बार फिर बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ गया है। बंगाल बीजेपी अब तुणमूल सुप्रीमो को घेरने की कोशिश कर रही है, उसी सिंगूर का इस्तेमाल करते हुए, जो कभी सिंगूर आंदोलन के दौरान ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्थान का मंच बना था। बीजेपी का दावा है कि सत्ता में आने पर वह टाटा को सिंगूर वापस लाएगी। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सिंगूर में एक जनसभा को संबोधित करने



पहुंचे। कोलकाता से लगभग 40 किलोमीटर दूर मौजूद सिंगूर, 2006-08 के दौरान राज्य की राजनीति में सबसे बड़े संघर्षों में से एक का केंद्र था। बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने टाटा नैनो कारखाने के लिए लगभग

1000 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण कर लिया, जिससे उस विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तत्कालीन विपक्षी नेता ममता बनर्जी इस आंदोलन का चेहरा बन गईं। भूमि आंदोलन जल्द ही राज्यव्यापी राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। सिंगूर आंदोलन पुलिस के साथ झड़पों, गिरफ्तारियों और कोलकाता में ममता की 21 दिनों की भूख हड़ताल के कारण सुर्खियों में रहा। टाटा मोटर्स ने आखिरकार 2008 में अपनी फैक्ट्री सिंगूर से गुजरात के साणंद में ट्रांसफर कर दी।

सिंगूर को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी

हालाँकि, लगभग दो दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सिंगूर को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का दावा है कि सिंगूर आंदोलन से आए राजनीतिक बदलावों के बावजूद, राज्य ने औद्योगीकरण का एक बड़ा अवसर खो दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने सिंगूर को ‘बंगाल के खोए हुए औद्योगीकरण का प्रतीक’ बताया और कहा कि टाटा को निष्कासित किए जाने के बाद से ही उद्योग राज्य छोड़कर चला गया है। उनका दावा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो टाटा को सिंगूर वापस लाया जाएगा। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि 18 जनवरी को मोदी की रैली में वे किसान भी शामिल हुए जिन्होंने कभी भूमि आंदोलन में भाग लिया था।

परिक्‍रमा



अरुण पटेल

लेखक
सुबह सवेरे के
प्रबंध संपादक हैं

‘स्मार्ट सिटी’ मॉडल पर गरजते-बरसते राहुल गांधी

दू षित पानी पीने से इंदौर में हुई मौतों और बीमार लोगों से मुलाकात के बाद लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्मार्ट सिटी मॉडल पर शाब्दिक हमला बोलते हुए कहा कि यह नया मॉडल है जहां पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। प्रभावितों के साथ अपने खड़े होने की बात कहते हुए राहुल गांधी ने एक-एक लाख रुपया और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पचास-पचास हजार रुपये के चेक सौंपे। राहुल गांधी का दो-टूक शब्दों में कहना था कि किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना चाहिए, क्योंकि यह समस्या सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं है बल्कि देश व प्रदेश के कई शहरों में भी यही स्थिति है। भाजपा सरकार साफ पानी और हवा जैसी बुनियादी सुविधाएं देने भी विफल रही है। इस त्रासदी के लिए किसी न किसी को तो जवाबदेह ठहराना चाहिए तथा पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिये। उनका आरोप था कि आज भी लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और लोग सिर्फ वही मांग कर रहे हैं जो एक सरकार का कार्य है कि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि नेता प्रतिपक्ष के रुप में जनता के मुद्दे उठाना मेरी जिम्मेदारी है, आप इसे राजनीति कहें या जो भी आपको उचित लगेवह कहें।

राहुल गांधी इंदौर आये और करीब साढ़े तीन घंटे तक इंदौर में रहे और इस बीच उन्होंने बाम्बे

अस्पताल पहुंचकर छह मरीजों व उनके स्वजनों से मुलाकात की। उसके बाद भागीरथपुरा में मृतका गीता के घर पहुंचे, फोटो पर फूल चढ़ाये तथा जमीन पर बैठकर परिवारजनों से बात की, वे यहां पर लगभग सात मिनट रुके और एक लाख रुपये का चेक दिया। इस बार राहुल गांधी बुलेट प्रूफ कार की जगह विपिन वानखेडे की सामान्य कार की अगली सीट पर सवार हो गये तथा अस्पताल



और भागीरथपुरा इसी गाड़ी से गये। राहुल गांधी के इंदौर प्रवास के दौरान राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी विधायक महेश परमार, फूलसिंह बैरैया और सत्यनारायण पटेल आदि उपस्थित थे। एयरपोर्ट पर ही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भागीरथपुरा पर बनी कांग्रेस की समिति की रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया था कि

लापरवाही से सप्लाई किए गए दूषित पानी से ही 24 मौतें हुई हैं।

पंचायत सचिवों की पौ बारह

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आम बजट के पूर्व ही एक प्रकार से पंचायत सचिवों की झोली में सौगातों की मूसलाधार झड़वी लगा दी। 23 हजार पंचायतों के पंचायत सचिवों

को अब 1300 रुपये का विशेष भत्ता दिया जायेगा। सचिव के निधन पर स्वजनों को दी जाने वाली डेढ़ लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुक्रममा नियुक्ति के बाद वापस नहीं ली जायेगी। अब पंचायत सचिवों का कार्यकाल 62 वर्ष की उम्र तक रहेगा। वहीं दूसरी ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सचिव के परिवारजनों को आयुष्मान कार्ड देने और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के कारण लंबित अनुक्रममा

नियुक्ति के मामलों का समाधान निकालने के लिए न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने की बात कही। पंचायत सचिवों की पंचायत में महत्ता रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पंचायत राज व्यवस्था में पंचायत सचिव योजनाओं और विकास कार्यों की धुरी हैं और यही सबसे कड़ी इकाई है। चाहे कितना ही बड़ा आईएएस अधिकारी क्यों न हो, प्रधानमंत्री या

सरकार के निर्णयों का कियान्वयन पंचायत स्तर पर ही होता है जिसमें पंचायत सचिव की भूमिका अहम् रहती है। हम रामराज्य की कल्पना करें तो पंचायत सचिव पंचायती राज में हनुमानजी की भूमिका में काम करते हैं।

और यह भी

मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने के

अभियान में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता व संगठन दोनों भिड़े हुए हैं और इसी दौरान आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के एक बड़े आदिवासी नेता उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि आदिवासी समाज और संस्कृति खत्म करने की साजिश की जा रही है। उनका कहना था कि हम जंगल, सूर्य, गाय,

बैल और फसल की पूजा करते हैं लेकिन आज देश में होने वाली सोलहवीं जनगणना में वह आदिवासी कोड नहीं मिल पा रहा है। कहीं यह हमारी पहचान को खत्म करने की साजिश तो नहीं है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदिवासी संस्कृति और समाज को खत्म करने की साजिश हो रही है। नेपालगर के चैनपुरा में 33वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन को सम्बोधित

करते हुए उमंग सिंघार ने इस बात पर जोर दिया कि हम संकल्प लें कि इस लड़ाई को योजनाबद्ध तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया और झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि प्रदेश में डेढ़ करोड़ समाज के लोगों का जापन राष्ट्रपति को भेजकर आदिवासी कोड के अधिकार की मांग की जायेगी।

युवती का शव दो दिन तक लटका रहा

इंदौर। मानसिक तनाव के चलते युवती ने मकर संक्रांति पर मां से बात की। कुछ देर बाद मां से कहा कि बाद में बात करती हूं। इसके बाद उससे बात नहीं हुई। दो दिन बाद आसपास के लोगों को बदबू आई तो युवती का शव कमरे में लटका मिला। युवती ग्राइवेट बैंक में काम करती थी। घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने युवती का मोबाइल कस्टडी में ले लिया है। उमंग पिता मालती प्रजापति मूल रूप से भोपाल की रहने वाली है। वह कुछ सालों से खंडवा रोड के गणेश नगर में फिरोज से रह रही थी। उसके घर में माता-पिता और छोटी बहन है। पिता भोपाल में व्यापार करते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद भोपाल से माता-पिता और अन्य परिजन इंदौर पहुंचे। एमवाय अस्पताल में उसका पीएम कराया जा रहा है। परिजन ने बताया कि शव को भोपाल ले जाया जाएगा, जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजन ने बताया कि 14 जनवरी को उमंग से आखरी बार बात हुई थी। ये भी बताया जा रहा है कि उस वक्त वह नाराज थी, जिस पर उसने मां से कहा था कि वह बाद में बात करेगी। दो दिन से युवती कमरे में से बाहर नहीं आई थी। न तो पड़ोसियों ने उसे देखा और मकान मालिक ने। वहीं परिवार के लोगों ने उसे शुक्रवार को कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। वे कमरे पर पहुंचे तो उसका शव लटका मिला।

शराब से भरी कार छोड़कर तस्कर फरार

इंदौर। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब से भरी कार जब्त की है। गड़बड़ी पुलिसिया के पास की गई इस कार्रवाई में चालक पुलिस को देखकर कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कार के माध्यम से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गड़बड़ी पुलिसिया के पास घेराबंदी की। इसी दौरान एक सट्रिच कार आती दिखाई दी। पुलिस को नजदीक आता देख चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन वाहन में खराबी आने के कारण वह कार को सड़क पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। लावारिस हालत में मिली कार में 7 बड़े कार्टन मिले, जिनमें 18 पेटियां अंग्रेजी शराब भरी हुई थीं। जब शराब की अनुमानित कीमत 2 लाख 31 हजार 456 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मालिक और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है।

फर्जी लिंक खोलते ही 2.92 लाख उड़े

इंदौर। शहर में साइबर ठगों ने ठगी का एक नया तरीका अपनाते हुए वाहन चालान के नाम पर लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। निजी कंपनी के कर्मचारी के मोबाइल पर ट्रैफिक चालान की फर्जी लिंक भेजकर उनके बैंक खाते से 2 लाख 92 हजार रुपए निकाल लिए गए। खजुराना क्षेत्र निवासी नितिन जैन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हाईकोर्ट के पास स्थित कार्यालय में कार्यरत हैं। गत 9 दिसंबर को कार्यालयीन समय में उनके मोबाइल पर सट्रिच यूपीके लिंक आया, जिसमें वाहन चालान जमा करने का संदेश लिखा था। किसी पुराने चालान की आशंका में नितिन ने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया, उनका मोबाइल हैक हो गया। लिंक खुलते ही कुछ ही सेकंड में उनके खाते से दो बार में राशि निकल गई। पहले 2 लाख और तुरंत बाद 92 हजार रुपए खाते से कट गए। पीड़ित ने तुरंत साइबर सेल और तुकोगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई।

तेज रफ्तार वाली कार ने मचाया कहर

इंदौर। मल्हारगंज क्षेत्र में शनिवार तड़के तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बड़ा हादसा कर बैठी। इतवारिया बाजार से मार्गमांज जाने वाले मार्ग पर सुबह करीब 3.45 बजे कार सड़क किनारे खड़े तीन दोपहिया वाहनों को टक्कर मारते हुए आयुर्वेदिक दवा की दुकान में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार दुकान में घुसने के बाद सड़क पर पलट गई। हादसे में दुकान का शटर पूरी तरह टूट गया और अंदर बना काउंटर करीब पांच फीट तक खिसक गया। बाहर बनी सीढ़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। दुकान मालिक शैलेंद्र दीधे ने बताया कि जोरदार धमाके की आवाज से पूरा परिवार नींद से जाग गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। बाहर देखा तो कार पलटी हुई थी और उसमें सवार दो युवक निकल मौके से फरार हो गए। हादसे में तीन में से दो दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि कार भोपाल पासिंग की है। कार के एयरबैग खुलने से उसमें सवार युवकों की जान बच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को जब्त किया और उसमें रख बीमा व अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए।

फेशियल के दौरान महिला के गहने गायब

इंदौर। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में स्थित नंद नगर में ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराने आई बुजुर्ग महिला का पर्स चोरी हो गया। पर्स में जेवरत और नकदी थे। फोनेवस टाउनशिप गणेश वाटिका में रहने वाली फरियादी कौशल्या गुर्जर ने बताया कि वे नंद नगर रोड नंबर 10 स्थित नव्या ब्यूटी पार्लर गई थीं। फेशियल से पहले उन्होंने मंगलसूत्र, कान के झाले और कांटे उतारकर पर्स में रख दिए थे। फेशियल के बाद जब उन्होंने पर्स देखा तो होश उड़ गए। पर्स में 27 ग्राम गहने और 10 हजार रुपए नहीं थे। पीड़िता ने पार्लर संचालिका उर्मिला जायसवाल और निधि जायसवाल पर चोरी का शक जताया है।

नियम तोड़ने पर आधा दर्जन स्लीपर बसों पर ‘आरटीओ’ कार्रवाई, धार में भी चेकिंग

कई बसों में पार्टीशन हटवाए, आपातकालीन उपकरणों की कमी पाई गई



दो दिन चला जांच अभियान

एआरटीओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि हमारी टीम ने तीन इमली रोड, तीन इमली बस स्टैंड, राजीव गांधी चौराहा और चोड़थराम रोड सहित विभिन्न स्थानों पर बस याई में जांच की। निरीक्षण के दौरान कई बसों में अवैध पार्टीशन दरवाजे हटवाए गए, कुछ में एफडीएसएस सिस्टम नहीं मिला और कई वाहनों में आपातकालीन उपकरणों की कमी पाई गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एक स्लीपर बस की फिटनेस तत्काल निरस्त कर दिया गया है। साथ ही निजी एटीएस सेटर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि मानकों पर खरी न उतरने वाली बसों की फिटनेस न करें।

इंदौर में है 489 स्लीपर बसें- आरटीओ के अनुसार इंदौर में कुल 489 स्लीपर बसें पंजीकृत हैं, जिनमें से 70 से अधिक फिलहाल ऑफ-रोड हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यात्री सुरक्षा से

कोई समझौता नहीं किया जाएगा और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

स्लीपर बसों के लिए नियम- बैठक में बताया गया कि स्लीपर बसों में ड्राइवर केबिन और यात्री केबिन

ऑटो की परमिट सीमा 60 किमी करने की मांग, सहमति हुई पर फैसला नहीं

डीसीपी ट्रैफिक से मिले ऑटो चालक, शहर में ऑटो का दबाव घटेगा



सीमा 60 किमी किए जाने से चालक उज्जैन, देवास, ओंकारेश्वर, धार और देपालपुर जैसे क्षेत्रों तक यात्रियों को ले जा सकेंगे। इससे यात्रियों को किरफायती और सुविधाजनक परिवहन मिलेगा, वहीं शहर के भीतर ऑटो रिक्शा का दबाव भी कम होगा।

फिटनेस के नाम पर वसूली - अपने ज्ञापन में रिक्शा चालकों ने फिटनेस टेस्ट के दौरान हो रही कथित अवैध वसूली और नंबर प्लेट के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूले जाने

की शिकायत भी उठाई। चालकों का कहना है कि इन अनियमितताओं से उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इस मामले पर डीसीपी ट्रैफिक आनंद कलादगी ने रिक्शा चालकों को आश्वासन दिया कि वे सभी संबंधित विभागों से समन्वय कर मामले का शीघ्र समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।

जन्मदिन के दिन युवक ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट भी नहीं मिला

इंदौर। जन्मदिन के बाद युवक ने सुसाइड कर लिया। जब उल्टी हुई तो परिवार को पता चला और चंद पलों में खुशियां गम में बदल गईं। युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी सांस हमेशा के लिए थम गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर एमवाय में उसका पीएम करवाया।

अन्नपूर्णा पुलिस के मुताबिक यह घटना महावर नगर की है। यहां रहने वाले वंश (20) पिता अनिल पारोचे का शुक्रवार को जन्मदिन था। परिवार में खुशी का माहौल था। परिवार के लोगों ने वंश का पूरे

उल्टी हुई तो अस्पताल ले गए

भाई ने बताया कि वंश को जब उल्टी हुई और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो मां को पता चला, जिसके बाद उसे प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया। नीरज ने बताया कि वंश धार्मिक प्रवृत्ति का था। पूजा-पाठ करने वाला था। उसे माताजी भी आती थी। वह मां के साथ नगर निगम में काम करता था। उसने ऐसा क्यों किया ये परिवार के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है। उसके पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है।

उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया। बड़े भाई नीरज ने बताया कि वे विदुर नगर में रहते हैं, लेकिन उनका पुराना मकान महावर नगर में है। शुक्रवार को छोटे भाई का जन्मदिन मनाया। जिसके बाद परिवार के लोगों ने खाना खाया। उसने भी खाया और वह ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे में चला गया। वहां उसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया।

जहरीला पदार्थ खाने से गई जान

अन्नपूर्णा थाने के सहायक उपनिरीक्षक चंद्रपाल सिंह यादव ने बताया कि जहरीला पदार्थ खाने के कारण वंश को अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां आज उसने दम तोड़ दिया। उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। एमवाय में उसका पीएम करवाया जा रहा है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

कानून और न्याय

विदेश यात्रा का अधिकार-2

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)



मे नका गांधी का पासपोर्ट 1 जून, 1976 को पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार जारी किया गया था। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (नई दिल्ली) ने 2 जुलाई, 1977 को उनसे अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा। याचिकाकर्ता ने इसे विदेश मंत्रालय के मनमाणा और एकतरफा फैसला बताया। बाद में, याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। इसमें दावा किया गया कि राज्य द्वारा उसके पासपोर्ट को जब्त करना अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन था। सतवंत सिंह साहनी बनाम रामारत्नम के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय के समक्ष अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे थे। क्या मौलिक अधिकार निरोपक्ष हैं या शर्तत हैं और भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए ऐसे मौलिक अधिकारों का दायरा कितना है? क्या अनुच्छेद 21 के तहत 'विदेश यात्रा का अधिकार' संरक्षित है या नहीं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के बीच क्या संबंध है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के दायरे का निर्धारण किया जाना चाहिए। क्या पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(सी) में निर्धारित प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यदि ऐसा है, तो क्या ऐसा विधान एक ठोस कानून है? क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी का विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है? याचिकाकर्ता को कहा था कि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का ही एक हिस्सा है, और किसी भी नागरिक को इस अधिकार से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक वह कानूनी प्रक्रिया का पालन न करे। इसके अलावा, 1967

विदेश जाना व्यक्तिगत आजादी के अधिकार का हिस्सा

‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ शब्द की व्याख्या प्रतिबंधित और कठोर अर्थ में नहीं, बल्कि उदार और व्यापक अर्थ में की जानी चाहिए। अनुच्छेद 21 विदेश जाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का ही एक हिस्सा है। किसी भी नागरिक को इस अधिकार से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक वह कानूनी प्रक्रिया का पालन न करे। इसके अलावा, 1967 के पासपोर्ट अधिनियम में पासपोर्ट धारक के पासपोर्ट को जब्त करने, रद्द करने या हिरासत में लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

के पासपोर्ट अधिनियम में पासपोर्ट धारक के पासपोर्ट को जब्त करने, रद्द करने या हिरासत में लेने का कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप, यह अधिनियम तर्कहीन और मनमाणा है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर न देकर केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया है। परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 21 का वास्तविक अर्थ, साथ ही इसकी प्रकृति और संरक्षण को स्थापित करना आवश्यक है। साथ ही किसी भी कानूनी प्रक्रिया में मनमानी नहीं होनी चाहिए और उसे 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' का पालन करना चाहिए। संविधान सभा के आशय को बनाए रखने और हमारे संविधान की भावना को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों को एक दूसरे के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए, और इस स्थिति में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा ऑर्डि अल्टरम पार्टम, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, प्राकृतिक न्याय का एक मूलभूत घटक है।

इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत ने संविधान के स्वरूप को तब बदल दिया जब उसने फैसला सुनाया कि हालांकि अनुच्छेद 21 का पाठ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

प्रावधानों का एक विशेष संबंध है और प्रत्येक कानून को उन अनुच्छेदों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा। न्यायालय ने माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्द की व्याख्या प्रतिबंधित और कठोर अर्थ में नहीं, बल्कि उदार और व्यापक अर्थ में की जानी चाहिए। अनुच्छेद 21 विदेश जाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है (जैसा कि सतवंत सिंह मामले में दावा किया गया है)। न्यायालय के अनुसार, धारा 10(3)(सी) और 10(5) प्रशासनिक आदेश हैं जिन्हें अनुचितता, दुर्भावना, प्राकृतिक न्याय से इनकार और अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। हमें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया के बीच अंतर करना होगा। एक गोपालन का मामला पहला ऐसा मामला था जब सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मूल्यांकन करने से इनकार कर दिया था। सरल शब्दों में कहें तो, यह विधानमंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कानून है जिसका पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि यह उचित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। इस अवधारणा के

अंतर्गत कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने का अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि विधिवत रूप से अधिनियमित कोई भी कानून वैध है, भले ही वह न्याय और निष्पक्षता के आदर्शों का उल्लंघन करता हो। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका मूल्यांकन दक्षता, न्यायसंगतता और गैर-मनमानी के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि कोई कानून तर्कसंगत, निष्पक्ष या मनमाना नहीं है, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला की रक्षा करता है। इस निर्णय के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल तत्व और इसे तैयार करने वाली संवैधानिक सभा के आशय को बनाए रखने के लिए एक प्रहरी की भूमिका ग्रहण की। अधिकांश न्यायाधीशों का मानना ​​था कि कोई भी कानून या प्रावधान न्यायसंगत, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, तो सबसे सुस्थापित या सर्वमान्य कानून को भी मनमाना कहा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले किसी भी नियम को अनुच्छेद 21, 14 और 19 के संवैधानिक मानदंडों पर खरा उतरना होगा। अनुच्छेद 21 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की भी रक्षा है, यह सुनिश्चित करते हुए करता है कि किसी को भी न्यायालय में अपनी बात रखने के अधिकार से वंचित न किया जाए। इसके अलावा, किसी भी सरकारी कार्रवाई या कानून को असंवैधानिक घोषित करने के लिए स्वर्ण त्रिकोण यानी अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उपयोग किया जाना चाहिए।

खेल

सचिन सिंह परिहार

लेखक राष्ट्रीय कराते खिलाड़ी हैं।



साल 2026 में भारत का खेल परिदृश्य केवल बदलाव के दौर से नहीं गुजर रहा, बल्कि वह एक नई पहचान गढ़ने की प्रक्रिया में है। हमने देखा है दशकों तक खेलों को भारत में ‘अतिरिक्त गतिविधि’ या ‘क्रिकेट तक सीमित उत्सव’ मानने की प्रवृत्ति रही, लेकिन आज खेल नीति, बजट, अवसरंचना और राजनीतिक प्राथमिकताओं के केंद्र में आ चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी, राज्यों के बीच खेल प्रतिस्पर्धा, निजी निवेश और स्वयं प्रधानमंत्री की सक्रिय भूमिका ये सभी संकेत देते हैं कि खेल अब भारत के लिए केवल मैदान की गतिविधि नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की रणनीति बन चुके हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप, हॉकी एशिया कप और बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जैसे आयोजनों की मेजबानी के साथ भारत स्वयं को एक ‘विश्वसनीय खेल आयोजक’ के रूप में स्थापित कर रहा है। लेकिन 2026 का सवाल केवल आयोजन तक सीमित नहीं है साथ ही कि क्या यह ऊर्जा प्रदर्शन, पदकों और स्थायी खेल संस्कृति में बदल पाएगी? अब 2026 में भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल है, जो एक साथ कई बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी कर रहे हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप के सफल आयोजन के साथ भारत ने 2026 में खेलों की दुनिया में एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा कर लिया है। यह आयोजन केवल एक टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि उस बदलती सोच का प्रमाण था जिसमें खेल

भारत का खेल पुनर्जागरण- 2026 की नई दिशा

अब भारत में हाशिये की गतिविधि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता बनते जा रहे हैं। स्टेडियमों की भरी हुई दर्शक दीर्घाएँ, रिकॉर्ड डिजिटल व्यूअरशिप और अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत न केवल बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी कर सकता है, बल्कि उन्हें जन आंदोलन में बदलने की क्षमता भी रखता है। यह लोकप्रियता केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आर्थिक भी है। विज्ञापन और प्रायोजन के आँकड़े संकेत देते हैं कि महिला क्रिकेट अब व्यावसायिक रूप से टिकाऊ हो चुका है। लेकिन चुनौती यह है कि क्या यह लोकप्रियता घरेलू ढाँचे जूनियर लीग, फिटनेस सिस्टम और कोचिंग की भी मजबूत कर पाएगी। हॉकी एशिया कप का आयोजन बिहार के राजगीर में होना भारतीय खेल नीति में आए भौगोलिक बदलाव का प्रतीक है। वहीं बॉक्सिंग वर्ल्ड कप का नोएडा में आयोजन यह दर्शाता है कि भारत अब गैर-पारंपरिक और व्यक्तिगत खेलों को भी वैश्विक मंच देने के लिए तैयार है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में खेलों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सक्रियता केवल भाषणों तक सीमित नहीं रही है। खिलाड़ियों से सीधा संवाद, अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं से मुलाकात, और ओलंपिक से पहले ‘मन की बात’ जैसे मंचों पर खिलाड़ियों का उल्लेख इन सबका मनोवैज्ञानिक प्रभाव स्पष्ट दिखाता है। 2026 में खेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच समन्वय पहले से अधिक संस्थागत हुआ है। ‘खेलो इंडिया’, ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ और

ओलंपिक तैयारी से जुड़े कार्यक्रमों को शीर्ष राजनीतिक संरक्षण मिला है। इसका असर यह हुआ है कि खेल अब केवल मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सरकारी प्राथमिकता बन गया है। 2036 ओलंपिक की मेजबानी की भारत की दावेदारी को भी इसी राजनीतिक इच्छाशक्ति के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालाँकि मेजबानी का सपना तभी सार्थक होगा, जब प्रदर्शन का आधार पहले से मजबूत हो। 2026-27 के केंद्रीय बजट में खेल मंत्रालय को लगभग ₹. 4,200 करोड़ का आवंटन मिला है, जो 2015 की तुलना में लगभग तीन गुना है। ‘खेलो इंडिया’ योजना के अंतर्गत देशभर में 1,000 से अधिक केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें से बड़ी संख्या ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में है। इन केंद्रों से जुड़े आँकड़े बताते हैं कि लगभग 60 प्रतिशत खिलाड़ी छोटे शहरों और गाँवों से आते हैं, और 40 प्रतिशत से अधिक खिलाड़ी पहली पीढ़ी के एथलीट हैं। यह बदलाव इस धारणा को तोड़ता है कि खेल केवल शहरी अभिजात वर्ग तक सीमित हैं। 2026 के खेल मानचित्र में मध्य प्रदेश का नाम विशेष रूप से उभरकर सामने आया है। लंबे समय तक ‘बीमारू राज्यों’ की श्रेणी में गिने जाने वाले इस प्रदेश ने खेल अवसरंचना में उल्लेखनीय निवेश किया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में आधुनिक स्टेडियम, शूटिंग रेंज और अकादमियाँ विकसित की गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित खेल अकादमियों विशेषकर एथलेटिक्स, शूटिंग, तैराकी और हॉकी

से निकले खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। राज्य का खेल बजट पिछले दस वर्षों में लगभग चार गुना बढ़ा है। इंदौर को स्पोर्ट्स साइंस और ट्रेनिंग हब के रूप में विकसित करने की योजना यह दर्शाती है कि मध्य प्रदेश अब केवल प्रतिभा आपूर्ति करने वाला राज्य नहीं, बल्कि खेल विकास का मॉडल बनना चाहता है। यह बदलाव बताता है कि खेलों में प्राति केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रह गई है। 2025 में लागू राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक का असर 2026 में दिखने लगा है। खेल संघों में आयु-सीमा, कार्यकाल सीमा और एथलीट प्रतिनिधित्व जैसे प्रावधानों के कारण कई संघों में संरचनात्मक बदलाव हुए हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, चयन से जुड़ी औपचारिक शिकायतों में करीब 30 प्रतिशत की कमी आई है। हालाँकि कुछ संघों में अब भी प्रतिरोध है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पारदर्शिता का सीधा संबंध प्रदर्शन से है। यदि भारत की तुलना जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया से की जाए, तो अंतर साफ़ दिखता है। भारत में प्रति खिलाड़ी खर्च अभी भी कम है, स्पोर्ट्स साइंस और रिकवरी सिस्टम सीमित हैं, स्कूल स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेलों का ढाँचा कमजोर है। हाल ही में जूनियर बास्केटबॉल और फुटबॉल टीमों के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन ने यह संकेत दिया कि टीम स्पोर्ट्स में भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है। इसके विपरीत, व्यक्तिगत खेलों जैसे शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में भारत की स्थिति

लगातार मजबूत हो रही है। नीति आयोग के 2026 के सर्वे के अनुसार, अब भी अधिकांश माता-पिता खेल को सुरक्षित करियर विकल्प नहीं मानते। यही कारण है कि किशोरावस्था में खेल छोड़ने वालों की संख्या अधिक है। हालाँकि शहरी मध्यम वर्ग में सोच बदल रही है। खेल अब ‘जोखिम’ नहीं, बल्कि ‘संभावना’ माने जाने लगे हैं। ग्रामीण भारत में चुनौती संसाधनों की है, लेकिन वहाँ से सबसे अधिक प्रतिभा भी सामने आ रही है। भारत यदि सचमुच खेल महाशक्ति बनना चाहता है, तो उसे तीन मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। वैज्ञानिक प्रशिक्षण और स्पोर्ट्स साइंस, कोचिंग और स्कूल खेलों का पुनर्गठन,खिलाड़ियों की सामाजिक आर्थिक सुखा। 2026 का भारत खेलों में न तो शुरुआती दौर में है, न ही मंजिल पर। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहाँ नीति, राजनीति और प्रतिभा एक साथ मौजूद हैं। अब चुनौती यह है कि यह संगम स्थायी परिणाम दे। खेल आज भारत के लिए केवल पदक नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, वैश्विक प्रतिष्ठा और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हैं। यदि आयोजन, निवेश और नेतृत्व को प्रदर्शन में बदला जा सका, तो आने वाला दशक भारत के लिए केवल खेलों का नहीं, बल्कि खेल नेतृत्व का दशक साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री जी की सक्रियता, राज्यों की प्रतिस्पर्धा और बढ़ता बजट सही दिशा में कदम हैं, लेकिन अंतिम परीक्षा मैदान पर होगी।

मुद्दा

आरबी त्रिपाठी

लेखक संभारक हैं



राजधानी भोपाल में प्रदूषण लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। खासकर पॉश एरिया कहे जाने वाले अरेरा कॉलोनी और उससे सटे त्रिलंगा, गुलमोहर इलाके में इसका असर ज्यादा है। बीते दिनों अरेरा कॉलोनी तथा पर्यावरण परिसर क्षेत्र में प्रदूषण 314 एक्यूआई तक पहुंच गया। इस तरह भोपाल का मुकाबला सीधे नई दिल्ली से हो रहा लगता है जहाँ प्रदूषण का एक्यूआई लगातार बढ़ता घटता रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां प्रदूषण के महेनजर प्रतिबंध लगाये गये हैं जिनमें निर्माण कार्यों पर रोक तथा धुंआ फैलाने वाले वाहन आदि शामिल है। खैर, देश की राजधानी की बात अलग है और तमाम संसाधन उपलब्ध है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ते प्रदूषण की वजह है सीमेंट कांक्रीट रोड या व्हाइट टॉपिंग सड़कों का निर्माण तथा सड़कों के बीचों-बीच सीवेज लाइनें डालने के लिये की जा रही खुदाई। दूसरी ओर मनमाने ढंग से हो रहे निर्माण कार्य जहां से धूलकण सर्दी के मौसम के चलते वातावरण में घुलकर मानव जीवन खासकर श्वासं तथा अन्य बीमारियों के रोगीय और सीनियर सिटीजन, छोटे बच्चों के लिए ज्यादा कष्टदायक बन रही है। कुछ समय पूर्व अरेरा कॉलोनी की अंदरूनी सड़कों तथा राजीव गांधी चौराहे से वंदे मातरम से दस नंबर मार्केट तक और इन दिनों ग्यारह सौ क्वार्टर के आगे कैम्पियन स्कूल से अहिल्याबाई प्रतिमा से त्रिलंगा की मुख्य रोड पर ऐसा ही काम चलने से ना केवल प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि एकतरफा रोड पर ट्राफिक के चलते इसमें भी बाधाये आ रही है। स्कूल बसों से लेकर पूरा ट्राफिक किसी

धूल धूसरित सड़कों के बीच गुलाबों की महक

कुछ समय पूर्व अरेरा कॉलोनी की अंदरूनी सड़कों तथा राजीव गांधी चौराहे से वंदे मातरम् से दस नंबर मार्केट तक और इन दिनों ग्यारह सौ क्वार्टर के आगे कैम्पियन स्कूल से अहिल्याबाई प्रतिमा से त्रिलंगा की मुख्य रोड पर ऐसा ही काम चलने से ना केवल प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि एकतरफा रोड पर ट्राफिक के चलते इसमें भी बाधाये आ रही है। स्कूल बसों से लेकर पूरा ट्राफिक किसी तरह एकल सड़क से गुजर रहा है। कई जगह दोपहिया वाहन चालक गिर पड़ रहे हैं। कुछ लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि दूसरों के लिये खतरा बन जाते हैं। लेकिन जिम्मेदारों को शायद ही इस बात की कोई परवाह हो।

तरह एकल सड़क से गुजर रहा है। कई जगह दोपहिया वाहन चालक गिर पड़ रहे हैं। कुछ लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि दूसरों के लिये खतरा बन जाते हैं। लेकिन जिम्मेदारों को शायद ही इस बात की कोई परवाह हो। सो, इंदौर में दूधित जल से लोगों की मौतों पर कोहराम अभी तक थमा नहीं है तो भोपाल में धूल धूसरित सड़कें लोगों की रोजाना की परेशानी बन रही है। कहीं भी कभी भी अच्छी खासी सड़कों को तोड़कर सीवेज लाइन डालने और सीसी रोड/ व्हाइट टॉपिंग रोड बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। ना कोई पूर्व सूचना और ना ही कोई एनाउंसमेंट। कई जगहों पर मकान, प्रतिष्ठान आदि के सामने इस तरह की सड़कों से नीचे हो जाने से अलग प्रकार की परेशानी आना संभावित है। सोचें भवन निर्माण कार्य में ग्रीन नेट आवश्यक रूप से लगाने का प्रावधान है लेकिन अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले इस काम में ऐसा कुछ नहीं।



नई दिल्ली की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहां हाल ही में एयरप्यूरीफायर के उपयोग से इसकी डिमांड बढ़ रही है। लंबे समय से घने कोहरे, ट्राफिक जाम के हालात और सर्दी के मौसम के चलते ऐसा हो रहा है। लेकिन इतना महंगा उपकरण कुछ लोगों का शगल हो सकता है ज्यादातर लोगों को तो इन समस्याओं से जुझना ही होगा। लगता है भोपाल, इंदौर तथा अन्य शहरों में भी इस उपकरण का उपयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। इन सबके बीच भोपाल की एक अच्छी खबर सुकून देने वाली थी। यहां पिछले दिनों आयोजित गुलाब तथा अन्य सीजनल फूलों की प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों, किस्मों के फूलों की बहार और मनमोहक खुशबू प्रकृति प्रेमियों के लिये किसी उपहार से कम नहीं था। यहां महकते फूल जैसे प्रदूषण को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे थे। पुष्प प्रेमियों और शौकीन लोगों ने इनका भरपूर आनंद उठाया। अनेक लोग अपने परिवारों के साथ मनपसंद फूलों के नजदीक सेल्फी और फोटो, वीडियो बनाते

दिखाई दे रहे थे। आजकल रील्स बनाने, वायरल करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है सो,यह उपक्रम भी किया जा रहा था। नई दिल्ली की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहाँ हाल ही में एयर प्यूरीफायर की डिमांड बढ़ गई है। घने कोहरे, बार-बार के ट्राफिक जाम, निर्माण कार्य की वजह से प्रदूषण फैलने के चलते लोगों खासकर श्वासं के मरीजों और सीनियर सिटीजन को बहुत तकलीफ उठाना पड़ती है। दिल्ली में कुछ दिन पहले प्रदूषण 354 एक्यूआई तक पहुंच गया। हालांकि इसके महेनजर वहां निर्माण कार्य पर रोक तथा डीजल चलित वाहनों के लिये प्रतिबंध लागू किये जाने की खबर भी है। यदि इसी दृतागत से प्रदूषण, शोरगुल बड़ता रहा तो आने वाले वक्त में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल जरूरी होते जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कालांतर में इसके लिये भी सब्सिडी मिलना शुरू हो जाये। यह उपकरण प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के खतरे को कम करने में मददगार होता है। हवा से प्रदूषक तत्वों को हटाकर हवा की क्वालिटी में सुधार लाता है।

लाडली बहना कार्यक्रम के अंतर्गत विदिशा में भव्य आयोजन

500 लाडली बहनों ने लिया उत्साहपूर्वक भाग

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता जी के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग, विदिशा द्वारा लाडली बहना कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक भव्य एवं उत्साहपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लाडली बहनों को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, बल्कि सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी सुदृढ़ करना रहा। इस अवसर पर जिले की कुल 500 लाडली बहनों ने सहभागिता की और कार्यक्रम को सफल बनाया।

कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत रूप से सरस्वती वंदना एवं कन्या पूजन के साथ की गई, जिससे कार्यक्रम का वातावरण भक्तिमय एवं प्रेरणादायक बन गया। इसके पश्चात लाडली बहनों के बीच पतंग प्रतियोगिता एवं रस्सा खींच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं ने महिलाओं के बीच आपसी सहयोग, टीम भावना एवं आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम के दौरान आजीविका मिशन एवं स्वास्थ्य



विभाग के सहयोग से सभी उपस्थित लाडली बहनों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने लाडली बहना योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना प्रदेश की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। उन्होंने महिलाओं से आत्मनिर्भर बनने , अपने स्वास्थ्य का ध्यान

रखने एवं बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वह क्षण रहा जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा नर्मदापुरम के माखननगर से वचुंअल माध्यम से राज्य की समस्त लाडली बहनों को एवं विदिशा की 2लाख 71 हजार बहनों को 40 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से योजना की किश्त जारी की गई। इस अवसर पर उपस्थित लाडली बहनों में अत्यधिक उत्साह देखने

को मिला। मुख्यमंत्री जी की इस पहल ने महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए उनके चेहरे भर आत्मविश्वास की मुस्कान ला दी। कार्यक्रम के अंत में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सभी लाडली बहनों को तिल-गुड़ भेंट कर शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को माननीय विधायक श्री मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा जी के स्वयं पुरस्कार वितरित किया गया। इस पहल ने कार्यक्रम में सांस्कृतिक एवं पारंपरिक रंग भर दिया और महिलाओं के बीच अपनत्व की भावना को और मजबूत किया। यह कार्यक्रम जिले स्तर के साथ साथ सभी 9 परियोजना एवं समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित किया गया। विदिशा जिला मुख्यालय पर संपन्न हुए उक्त कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा, परियोजना अधिकारी श्री संजय सिंह एवं श्रीमती कृतिका व्यास, जिला समन्वयक श्री अरविंद मिश्रा, सरक्षण अधिकारी श्री संतोष रघुवंशी सहित कुल 25 पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई।



कलेक्टर ने किया सारू-मारू की गुफाओं की निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने बुधनी तहसील के ग्राम पान गुराड़िया स्थित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व की सारू-मारू की गुफाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गुफाओं, बौद्ध स्तूपों एवं शिलालेखों का अवलोकन किया और प्राचीन धरोहर के संरक्षण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने यह भी कहा कि सारू-मारू की गुफाएं जिले की ऐतिहासिक पहचान हैं। उल्लेखनीय है कि सारू-मारू की गुफाएं सीहोर जिले की बुधनी तहसील अंतर्गत ग्राम पान गुराड़िया के समीप स्थित एक प्राचीन बौद्ध मठ परिसर एवं पुरातात्विक स्थल हैं, जिनका संबंध तथागत गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्यों महामोद्गलायन और सारिपुत्र के काल से माना जाता है। यह स्थल सांची से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है और यहां प्राकृतिक गुफाओं के साथ-साथ अनेक बौद्ध स्तूप निर्मित हैं। गुफाओं में स्वस्तिक, त्रिरत्न एवं कलश जैसे बौद्ध प्रतीकों के भित्तिचित्र आज भी देखे जा सकते हैं, जो इस स्थल की धार्मिक एवं ऐतिहासिक महता को दर्शाते हैं। इस स्थल का विशेष महत्व इस कारण भी है कि यहां मुख्य गुफा में सम्राट अशोक से संबंधित दो महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुए हैं।

संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों हेतु अधिकारियों को सौंपे दायित्व

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर रायसेन में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिला स्तरीय समारोह के भव्य एवं गरिमामय आयोजन हेतु दायित्व सौंपते हुए व्यवस्थाएं, तैयारियां पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को रायसेन में सागर रोड स्थित शासकीय कन्या विद्यालय ग्राउंड पर आयोजित होगा। जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील, जनपद स्तर, शैक्षणिक संस्थाओं तथा ग्राम पंचायतों में गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में परेड, देशभक्ति से ओत-प्रोत शालेय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, कार्यक्रम स्थल पर अतिथियों तथा आमजन के आमगन-निर्गमन, बैठक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पेयजल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजना, कार्यक्रम और अन्य उपलब्धियों को रेखांकित करने वाले झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के एक दिन पूर्व जिले के सभी सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व की इमारतों पर प्रकाश की व्यवस्था करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

शासकीय महाविद्यालय भैंसदेही में रोजगार मेला 21 जनवरी को

बैतूल (निप्र)। मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में युवा संगम के तहत 21 जनवरी को प्रातः 11 से 4 बजे तक शासकीय महाविद्यालय भैंसदेही में रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी एवं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। रोजगार मेले में 14 कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। रोजगार मेले में यहां कंपनी रहेगी मौजूद जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि वर्धमान फैब्रिकस प्राइवेट लिमिटेड बुदनी में मशीन ऑपरेटर के 100 पदों, आयथार सीआईआई कौशल विकास पोथमपुर में ट्रेनी वर्कर के 100 पदों, कुलोदय टेक्नोपैक प्राइवेट लिमिटेड दमन गुजरात में मशीन ऑपरेटर मैकेनिक हेल्पर के 100 पदों, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन भोपाल में ट्रेनी वर्कर के 50 पदों तथा ट्राईटेंट प्राइवेट लिमिटेड बुदनी में मशीन ऑपरेटर के 100 पदों के लिए योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई होना आवश्यक है। इसी प्रकार यशस्वी ग्रुप भोपाल में अप्रेंटिस के 50 पदों तथा क्वेस कॉर्प बैंगलोर में अप्रेंटिस के 50 पदों के लिए योग्यता 12वीं, आईटीआई डिप्लोमा होना जरूरी है। सिपेट भोपाल में मशीन ऑपरेटर ट्रेनी के 50 पद तथा अंबुजा सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड छिंदवाड़ा में मशीन ऑपरेटर, ट्रेनी के 40 पदों के लिए योग्यता 10वीं, 12वीं, आईटीआई डिप्लोमा होना आवश्यक है। फुटवियर डिजाइनर एवं डेवलपमेंट छिंदवाड़ा में ट्रेनी वर्कर के 50 पद के लिए योग्यता 10वीं, 12वीं, आईटीआई और शक्ति मोटर्स मूलतः प्राइवेट लिमिटेड मूलताई में सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, मैकेनिक के 25 पदों के लिए योग्यता 8वीं से स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है। ग्लेटे कॉर्प सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नागपुर में अप्रेंटिस के 50 पदों के लिए योग्यता 10वीं 12वीं आईटीआई स्नातक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम प्राइवेट लिमिटेड में बीमा सखी, ग्रामीण बीमा अभिकर्ता के 50 पदों के लिए योग्यता 12वीं से स्नातक एवं आरएफएमआई ग्रुप बैतूल में ऑफिस, फील्ड वर्क, मार्केटिंग, टेलीकॉलिंग के 50 पदों के लिए योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक होना आवश्यक है।

जिला अस्पताल में ऑटोमेटिक मशीन से हेवी पल्लोर की सफाई

रायसेन (निप्र)। जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर और त्वरित उपचार के साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सीएमएचओ तथा सिविल सर्ज को दिए गए हैं। इसी कड़ी में जिला अस्पताल में ऑटोमेटिक मशीन से सफाई की जाएगी। शुक्रवार को जिला अस्पताल में सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री, सिविल सर्जन डॉ यशपाल बाल्यान सहित अन्य चिकित्सकों की उपस्थिति में सफाईकर्मी द्वारा ऑटोमेटिक मशीन से पल्लोर सफाई का शुभारंभ किया गया। सीएमएचओ डॉ खत्री ने बताया कि जिला अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाईजर पदों की भर्ती हेतु जनपद पंचायतों में आयोजित किए जा रहे हैं शिविर

रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले में संस्था एसएससीआई नीमच द्वारा जनपद पंचायत स्तर पर जिला पंचायत और मप्र डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए भर्ती शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में संस्था एसएससीआई नीमच द्वारा युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराते हुए सुरक्षा गार्ड तथा सुपरवाईजर पद पर युवाओं का चयन किया जाएगा। जिले की बाड़ी जनपद पंचायत प्रांगण में 19 जनवरी को, औबेदुल्लागंज जनपद पंचायत प्रांगण में 20 जनवरी को, सांची जनपद पंचायत प्रांगण में 21 जनवरी को और जिला रोजगार कार्यालय रायसेन में 22 जनवरी को यह शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में ऐसे युवा जिनकी आयु 21 से 40 वर्ष, ऊंचाई 168 सेमी हो, वजन 55 किलोग्राम व शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम हाईस्कूल (10वीं) उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण हो, सम्मिलित हो सकते हैं।



सुरक्षित कार्य स्थल हर महिला का अधिकार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन

बैतूल (निप्र)। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान जनक कार्य वातावरण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों की जा रही है। जिसके तारतम्य में कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन के निर्देशन में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत जिले में विभिन्न शासकीय, अशासकीय संस्थाओं में आंतरिक परिवार समिति एवं स्थानीय परिवार समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत सभा कक्ष में 16 जनवरी को किया गया।

जिसमें जिले की स्थानीय परिवार समिति की सदस्य श्रीमती अनिता पटेल उप जिलाध्यक्ष द्वारा कार्यशाला के प्रांरभ में

एक्ट के तहत आने वाली शिकायतों, उनके निपटान में आने वाली चुनौतियों के बारे में अवगत कराया गया। भोपाल मास्टर ट्रेनर एडवोकेट वंदना त्रिपाठी द्वारा उपस्थित सभी प्रतिभागियों को पॉश एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पोश एक्ट महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल, उत्पीड़न की रोकथाम, आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) के गठन और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाता है, जिसमें सुरक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर, जागरूकता और सांस्कृतिक बदलाव लाना भी शामिल है। ताकि महिलाएं बिना किसी डर के सम्मान के साथ काम कर सकें और यौन उत्पीड़न (मौखिक, शारीरिक या अन्य) से मुक्त वातावरण मिले। अंत में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री गौतम अधिकारी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण 19 से

बैतूल (निप्र)। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के ईएसडीपी कार्यक्रम के तहत बैतूल जिले में 19 जनवरी से 25 जनवरी तक सात दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। यह कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों में वैधानिक आवश्यकताएं विषय पर आधारित रहेगा तथा प्रतिदिन दोपहर 01 बजे से सायं 05 बजे तक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण उन उद्यमियों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्वयं का उद्योग व्यवसाय संचालित कर रहे हैं या इससे संबंधित उद्योग व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं। कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रबंधन सहित बैतूल जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अवसर व संभावनाएं, सहयोगी अधीक्षरचनात्मक सुविधाएं, शासन की ऋण अनुदान योजनाओं, वैधानिक औपचारिकताओं, लायसेंस लेने की नियम प्रक्रिया, गुमाफा एक्ट आदि के संबंध में जानकारी भी प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाएँ (सभी वर्ग की) और अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) के युवा-युवतियां की भागीदारी बढ़ाना, ताकि वे प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। यह कार्यक्रम उद्योगिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

चारों प्रकार के रेशम की डोर को मजबूती प्रदान करता प्रदेश का एकमात्र जिला नर्मदापुरम

मलवरी, टसर, ईरी और मूंगा रेशम उत्पादन से प्रदेश में नर्मदापुरम जिले ने बनाया नया मुकाम

नर्मदापुरम (निप्र)। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले को राज्य में रेशम उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी जिले के रूप में जाना जाता है। जिले में चार प्रकार के रेशम – मलवरी, टसर, ईरी और मूंगा का उत्पादन होता है। जिले के अधीनस्थ 16 मलवरी रेशम केंद्र और 12 टसर रेशम केंद्र सक्रिय रूप से संचालित हैं, जिससे किसानों और स्थानीय महिलाओं को रोजगार एवं आय का महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त हो रहा है। मालाखेड़ी सिल्क कैम्पस में फार्म से फेब्रिक तक उत्पादन गतिविधियों संचालित हैं। वर्ष 2025 में मालाखेड़ी केंद्र में 742 किलोग्राम मलवरी रेशम



धागा उत्पादन हुआ, जिसमें 32 महिलाओं को 5.78 लाख रुपये की मजदूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 415 किलोग्राम धागे की टि्वरिंग में

10 महिलाओं को 2.50 लाख रुपये की मजदूरी दी गई। शासकीय रेशम ककून मार्केट, मालाखेड़ी के माध्यम से 13,781 किलोग्राम ककून अन्य राज्यों

जैसे पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के व्यापारियों को उपलब्ध कराए गए, जिससे महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। मालाखेड़ी सिल्क यूनिट ने 12.00 लाख रुपये

प्रकार किसानों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2025 की मुख्य उपलब्धियाँ

मलवरी रेशम ककून उत्पादन - 15,426.5 किलोग्राम, जिससे 255 हितग्राहियों को लाभ मिला है। इसी प्रकार टसर ककून उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 2.68 लाख किलोग्राम वृद्धि हुई है। इसके साथ ही मूंगा रेशम का उत्पादन पचमढ़ी रेशम केंद्र में 5 एकड़ क्षेत्र में पौधरोपण और 500 नग ककून उत्पादन हो रहा है। मलवरी पौधों का रोपण - 27,500 पौधे, जिससे भविष्य में ककून उत्पादन में और वृद्धि होगी। जिले की रेशम गतिविधियों से अब तक 45 महिलाएँ 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं, जिससे महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। मालाखेड़ी सिल्क यूनिट ने 12.00 लाख रुपये

आगामी योजनाएं

रेशम उत्पादकों के लिए फार्म प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना करना है। इसी के साथ सिल्क समग्र 2 योजना के लागू होने से रेशम क्षेत्र का विकास और किसानों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

